

# सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस में दखल देने से इनकार, कहा- देश को डॉक्टरों की जरूरत

# मल्लिकार्जुन खड़गे का शिक्षा मंत्री पर हमला, मांगा इस्तीफा

नई दिल्ली, 24 जून। चिकित्सा शिक्षा का सपना देखने वाले युवाओं के संघर्ष और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े संदेश सामने आए हैं। देश में डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा शिक्षा की सुलभता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद मानवीय और व्यावहारिक रुख अपनाया है। एक तरफ जहां कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने में दखल देने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों की विशेषज्ञता को जनहित के लिए अनमोल बताया। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस

बहुत ज्यादा है। राजस्थान के एक मेडिकल छात्र ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस 18.90 लाख से 25 लाख रुपये के बीच है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कोई मेधावी छात्र डॉक्टर कैसे बनेगा? याचिकाकर्ता छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नोट-यूजी)-2025 में शामिल हुआ था। जस्टिस बी.वी. नागराज और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने इस दर्द को समझा, लेकिन



व्यावहारिक पक्ष रखते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, 'हमें इस देश में डॉक्टरों की जरूरत है।' लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति यह मांग नहीं कर सकता कि स्व-वित्तपोषित (प्राइवेट) संस्थान भी सरकारी संस्थानों के बराबर ही फीस वसूलें। कोर्ट ने छात्र को याद दिलाया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) का विकल्प हमेशा खुला रहता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु का एक और संवेदनशील मामला आया। 'तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन' ने याचिका दायर कर मांग की थी कि शैक्षणिक वर्ष

2025-2026 के लिए खाली रह गई 152 इन-सर्विस सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों को 'अखिल भारतीय कोटा' में सरेंडर करने से रोका जाए। इस मामले पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया और केंद्र एवं तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने सरकारी डॉक्टरों की भूमिका की सराहना करते हुए एक बेहद भावपूर्ण टिप्पणी की - 'एक सरकारी डॉक्टर अगर उच्च कौशल और विशेषज्ञता हासिल करता है, तो वह किसी निजी डॉक्टर की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतर सेवा कर सकेगा।' कोर्ट ने माना कि सेवा में रहते हुए पढ़ाई करने वाले डॉक्टर एक विशेष श्रेणी में आते हैं।

नई दिल्ली, 24 जून। कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने और परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों का अपमान करने का आरोप लगाया। पर एक पोस्ट में, खड़गे ने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल के दौरान 90 पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि टूट्टू पेपर लीक विवाद के कारण 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। खड़गे ने कहा कि 90 बार पेपर लीक हुए हैं, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है, NEET पेपर लीक की वजह से 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी है और कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। लेकिन मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी



से चिपके हुए हैं और इंटरव्यू देते समय 'स्टूडेंट्स इको' को 'आतंकवादी' कह रहे हैं। कंग्रेस अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को देश-विरोधी करार देती है। कंग्रेस के विरोध-प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले प्रदर्शनकारी किसानों को आंदोलन-जीवी और परजीवी कहा था। खड़गे ने जोर देकर कहा कि छात्रों का आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ रहा है और उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की मांग की। देश यह नहीं भूला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संसद में किसानों के हितैषियों को अपमानजनक ढंग से 'आंदोलन-जीवी' और 'परजीवी' कहा था। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस सरकार से सवाल करता है, उसे देश-विरोधी कहा जाता है। 'छात्रों की गुंज' पूरे देश में जोरदार ढंग से सुनाई देगी। मोदी सरकार के मंत्री प्रधान को इस्तीफा देना होगा। इससे पहले, एक इंटरव्यू में प्रधान ने कहा था कि जंतर-मंतर पर उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन विघटनकारी तत्वों की 'बी-टीएम' हैं। इंटरव्यू में प्रदर्शनकारियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विघटनकारी तत्वों की 'बी-टीएम' हैं। जो लोग लोकतंत्र में नकार दिए गए थे, वे अब भेष बदलकर आए हैं और सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं।

# भारी बारिश भूस्खलन और बाढ़ ने मचाई तबाही, 5 लोग लापता

अरुणाचल प्रदेश, 24 जून। अरुणाचल प्रदेश के केथी पन्थोर जिले में बुधवार को मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से कम से कम पांच लोग लापता हो गए और 17 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 18 मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं, विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुलु ने बताया कि याजाली सर्कल के अंतर्गत पूसा के पास नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) परियोजना कॉलोनी से लापता हुए लोगों की पहचान एलेश मराक (13), बालारी मराक (30), ताओ अंजीना (46), निर्मला गुप्ता (35) और सौरव



कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। अधिकारी ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण निमाणांधीन सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे कॉलोनी और आसपास के निचले आवासीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पानी भर गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कम से कम 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कर्मियों ने याजाली जलाशय से बिशु सिन्हा नामक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला, जबकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के एक वैज्ञानिक को इस आपदा से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग-13 के एक हिस्से से बचाया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और क्षेत्राधिकारी को नुकसान का आकलन करने और बचाव कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए तत्काल प्रभावित स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है।

# मुंबई के कलाकार आद्या श्रीवास्तव और दूरदर्शन कलाकार अविजित श्रीवास्तव की प्रस्तुति विश्व संगीत दिवस पर लगाया चारचांद

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था सुर ताल संगम द्वारा विश्व संगीत दिवस एवं विश्व योग दिवस के अवसर पर उद्यान भवन ऑडिटोरियम, हजरतगंज लखनऊ में एक भव्य संगीतमय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य, विविध मनोरंजन एवं पारिवारिक भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस विशेष आयोजन में विश्व संगीत दिवस, विश्व योग दिवस, फादर्स डे तथा महान पारवर्गायिका आशा भोंसले को समर्पित संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में आद्या सिंह, युविका पांडेय, त्रिनभ साहू, वैष्णवी पांडेय, अद्विका श्रीवास्तव, ईशानदिनी जादौन, भुवि सरन,



अक्षिता दीक्षित, रैना कपूर, आन्या गोयल, ईशा श्रीवास्तव, संगीता शुक्ला, अनुष्का शुक्ला, निर्मला अवस्थी, श्रद्धा प्रतिहारी, समीक्षा सिंह, बिपाशा बनर्जी, मनीष मिश्रा, डॉ शोएब अहमद आदि ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में संगीत प्रशिक्षक और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक अविजित श्रीवास्तव और मुंबई निवासी कुशल नृत्यांगना एवं गायिका आद्या श्रीवास्तव के निर्देशन में लाइव सिंगिंग, मनमोहक नृत्य प्रदर्शन, रोचक गेम्स, म्यूजिकल विज्व एवं आदि ने आयोजन को चार चांद लगा दिए। इसके साथ ही

प्रसिद्ध जादूगर शांका द्वारा प्रस्तुत मैजिक शो और योग प्रशिक्षिका संगीतिका ने योग ध्यान से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिवंगत सुप्रसिद्ध पारवर्गायिका सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि देते हुए विशिष्ट अतिथि श्रीमती संगीता जायसवाल ने रहे न रहे हम गीत प्रस्तुत किया। मुंबई से आमंत्रित सुप्रसिद्ध कलाकार आद्या श्रीवास्तव ने आशा भोंसले की श्रद्धांजलि के तौर पर उमराव जान की गजलें और भावनृत्य पेश करके सभी का मन मोह लिया। विश्व योग दिवस पर विशेष प्रस्तुति आदित्यगोपी गीत के माध्यम से लोकप्रिय गायक अविजित श्रीवास्तव देकर खूब वाहवाही बटोरी। मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान, एमएलसी सीतापुर सहित अनेक गणमान्य लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बतौर विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी नवीन श्रीवास्तव, श्री अनूप श्रीवास्तव, तारिक खान, आदित्य शर्मा, यश भारती सम्मानित पं केवल कुमार, दिल्ली निवासी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से विभूषित सुश्री रीना टंडन समेत आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। संस्था के संरक्षक श्री राजेश जायसवाल (आक्मीजन मैन) और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव एवं सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर सभी अतिथियों का शाल, बुके, स्मृति चिन्ह आदि भेंट करके स्वागत सम्मान किया। पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों के लिए सर्राइज गिफ्ट और फूड पैकेट वितरित किए गये।

# भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट करेंगे सहयोग, एमओयू पर हस्ताक्षर



नई दिल्ली। भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में एक सहमति पत्र पर (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर मंगलवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत और रूस के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस इगोर क्रास्नोव ने हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जस्टिस सुर्यकांत ने रूसी प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार, यह बैठक दोनों देशों के ऐतिहासिक और सामयिक रिश्तों पर जोर देते हुए शुरू हुई। बातचीत में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत, दोनों देशों की न्यायपालिका द्वारा किए गए डिजिटल बदलाव (न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने व न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए तकनीक व एआई को शामिल करना) और उच्च गुणवत्ता वाली न्यायिक शिक्षा का महत्व शामिल था। विस्तृत बातचीत के बाद हस्ताक्षरित एमओयू में सीखने के मकसद से यात्राएं, अल्पकालिक व दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और संयुक्त संगोष्ठियों व सम्मेलनों के जरिये सहयोग की प्रतिबद्धता जताई गई।

नियुक्तियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत, दोनों देशों की न्यायपालिका द्वारा किए गए डिजिटल बदलाव (न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने व न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए तकनीक व एआई को शामिल करना) और उच्च गुणवत्ता वाली न्यायिक शिक्षा का महत्व शामिल था। विस्तृत बातचीत के बाद हस्ताक्षरित एमओयू में सीखने के मकसद से यात्राएं, अल्पकालिक व दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और संयुक्त संगोष्ठियों व सम्मेलनों के जरिये सहयोग की प्रतिबद्धता जताई गई।

# ट्रंप को दोहरा झटका: सीनेट से पहली बार युद्ध शक्तियों से जुड़ा प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन, 24 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर अपनी नीतियों और शक्तियों पर दोहरा झटका लगा है। पहला झटका सीनेट से लगा, जबकि दूसरा झटका एक जज ने दिया। संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने पहली बार युद्ध शक्तियों से जुड़ा एक प्रस्ताव को पारित किया है। इसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय पारित



किया गया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए ट्रंप प्रशासन ने संसद से 80 अरब डालर की अतिरिक्त राशि मांगी है। सीनेट ने मंगलवार को वार पावर्स रिजोल्यूशन (राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों से जुड़ा प्रस्ताव) को

मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को 50-48 मतों से पारित किया गया। यह 10वीं बार रहा, जब सीनेट ने युद्ध रोकने की कोशिश की। हालांकि यह प्रस्ताव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है और इसका कानूनी प्रभाव नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि अमेरिकी संसद के दोनों सदन सीनेट और प्रतिनिधि सभा युद्ध और ट्रंप द्वारा ईरान के साथ किए गए समझौते को

लेकर चिंतित हैं। इस महीने की शुरूआत में प्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 1973 में वार पावर्स रिजोल्यूशन (जिससे आमतौर पर वार पावर्स एक्ट के नाम से जाना जाता है) के लागू होने के बाद यह पहली बार है, जब दोनों सदनों ने राष्ट्रपति को अमेरिकी सेनाओं को युद्ध से हटाने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित किया है।

**TIWARI'S SARASWATI CLASSES**  
Since 1992  
Parents' First Choice for 34+ Years  
Prof. Dr. Dayanand Tiwari  
Founder & Academic Director

**ADMISSIONS OPEN**  
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE  
NEET | JEE | MHT-CET  
10 DAYS FREE DEMO  
Attend Classes • Experience Our Teaching  
Take Admission After Satisfaction  
(No Hidden Conditions)

- 34+ Years of Academic Excellence
- Experienced & Dedicated Faculty
- Personal Attention
- Printed Notes & Regular Tests
- Strong Foundation for Boards & Competitive Exams

**Santacruz Branch**  
101 Sai Chambers,  
Opp. Santacruz Railway Station (East),  
Near Depot, Santacruz (E), Mumbai 400055

**Sion Branch**  
Opp. SIES College (Old),  
Near Gaurishripa Hotel,  
Sion (West), Mumbai

Limited Seats / Small Batch Size  
CALL NOW:  
**7738007373**

**DAKS REHAB CENTRE**  
(PARALYSIS PHYSIOTHERAPY CENTER AND OLD AGE HOME)

Contact us: 9820519851

विलडिंग नंबर 3, फ्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीवी नगर मुंबई-37

- Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- चिकित्सा उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

**NEW LIGHT CLASSES**  
TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg.  
Near Dianond Talkies,  
L. T. Road, Borivali (West)  
Mumbai - 400 092  
Maharashtra

**ADMISSIONS OPEN**  
ALL OVER INDIA  
ENROLL NOW

**SMART CLASSROOM**  
(ONLINE/OFFLINE)  
Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

## स्मार्टफोन संयमित उपयोग की वैश्विक जरूरत



-ललित गर्ग

विज्ञान और तकनीक ने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज का युग डिजिटल युग है, जहाँ एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट आई है। स्मार्टफोन ने संचार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक संबंधों को नई दिशा दी है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी लेकर आती है। स्मार्टफोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जितना बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज विश्वभर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्मार्टफोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, वैश्विक और अनुशासन के अभाव में इसका नकारात्मक पक्ष अधिकांश मुश्किल हो रहा है। स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, एकाकीपन, हिंसक प्रवृत्तियों, अश्लीलता, साइबर अपराध और सामाजिक घमाटन का कारण बन रही है। यही कारण है कि आज केवल परंपरागत समाज और विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं।



हाल ही में भारत के हरियाणा के नूह जिले के सुखपुरी गांव की पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गांव की पहचान साइबर अपराध के केंद्र के रूप में बनने लगी थी। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्मार्टफोन त्यागने और बैसिक फोन अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल मोबाइल तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि समाज की उस पीढ़ी की अभिव्यक्ति है, जो तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। गांव के युवाओं का विरोध भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज शिक्षा, रोजगार, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है- क्या समाधान तकनीक का बहिष्कार है या उसके विवेकपूर्ण उपयोग का संस्कार? विश्व के अनेक देशों ने इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन अग्रंथ कर दिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नोर्दलैंड, चीन और अमेरिका जैसे देशों में बच्चों और किशोरों के स्मार्टफोन उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में अनेक पहलें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग पर आयु-सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू किया है। ब्रिटेन में भी स्कूलों में मोबाइल उपयोग को सीमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हुए हैं और उन पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को रक्षा करना है।

वास्तव में स्मार्टफोन जहां वरदान है, वहीं अभिशाप भी है। इससे ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध है और भ्रम का संसार भी। यह शिक्षा का माध्यम भी है और अश्लीलता तथा हिंसा का प्रवेश-द्वार भी। यह रोजगार के अवसर भी देता है और साइबर अपराध की राह भी खोलता है। आज अनैतिक युवा रातों-रात अमीर बनने की लालसा में साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन जुआ और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराधों में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री, फेक न्यूज, नफरत और ट्रेल संस्कृति ने सामाजिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। सबसे अधिक चिंता का विषय बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। नांद में कमी, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। परिवारों में संवाद कम हुआ है और डिजिटल निकटता के बावजूद भावनात्मक दूरियां बढ़ी हैं। बच्चे खेल के मैदानों से दूर होकर आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं। विशेषतः स्मार्टफोन एक दुधारी तलवार है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एआई जहां शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, वहीं इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो, साइबर ठगी, पहचान की चोरी, फेक न्यूज और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराधों में एआई का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है। स्मार्टफोन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम बन गया है। एक साधारण मोबाइल फोन के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति एआई आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग कर नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार कर सकता है, भ्रामक सूचनाएं फैला सकता है या साइबर अपराधों को अंजाम दे सकता है। विशेष रूप से किशोर और युवा, जिनके पास तकनीकी कौशल तो है लेकिन नैतिक प्रशिक्षण और जिम्मेवता का अभाव है, वे अनजाने में अथवा त्वरित लाभ की लालसा में ऐसे कृत्यों में संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि एआई और स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डिजिटल नैतिकता, मानवीय मूल्यों और कानूनी जिम्मेदारियों का भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि तकनीक मानवता के विकास का साधन बने, विनाश का नहीं। आज संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है- ह्यविज्ञान बिना विवेक के विनाश का कारण बनता है, जबकि विवेक के साथ वही विज्ञान मानवता का वरदान बन जाता है। ऐसी स्थिति में भारत में भी व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यदि भारत को विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, तो उसे तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। भारत द्वारा निर्मित नीतियां न केवल स्वयं, बल्कि विश्व के लिए भी मार्गदर्शक बन सकें। इन दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं- पहल, बच्चों और किशोरों के लिए स्मार्टफोन उपयोग की आयु-सीमा और समय-सीमा निर्धारित की जाए। एक निश्चित आयु तक बच्चों को केवल आवश्यक और नियंत्रित डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

दूसरा, स्कूलों में साइबर साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं, बल्कि उसके दुष्परिणामों और कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों को डिजिटल पैरेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। पच्चों को मोबाइल भ्रामक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती-उन्हें मार्गदर्शन, संवाद और संस्कार भी देने होंगे। चौथा, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हानिकारक और अश्लील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण, आयु सत्यापन और एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पांचवां, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और रचनात्मक अवसरों का विस्तार किया जाए, ताकि वे त्वरित धनार्जन के प्रलोभन में अपराध की ओर न बढ़ें। भारतीय संस्कृति संवेद संयम की संस्कृति रही है। हमारे ऋषियों ने सिखाया है कि किसी भी साधन का मूल्य उसके उपयोग में निहित होता है। आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है-दोष आग का नहीं, उपयोगकर्ता का होता है। यही बात स्मार्टफोन पर भी लागू होती है। आज आवश्यकता डिजिटल दुनिया से कटने की नहीं, बल्कि डिजिटल जिम्मेदारी, साइबर साक्षरता और संयमित उपयोग की है। तकनीक का विरोध समाधान नहीं है, बल्कि उसके साथ नैतिकता, विवेक और मानवीय मूल्यों का समन्वय ही स्थायी समाधान है। स्मार्टफोन मानव की सेवा का साधन बने, मानव का स्वामी नहीं-इसी में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण निहित है।

## ईरान, होर्मुज और बदलती विश्व व्यवस्था



- महेंद्र तिवारी

विश्व राजनीति में शक्ति का अर्थ समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में शक्ति के मानक बदलते रहे हैं। कभी विशाल और अजेय सेनाएं किसी साम्राज्य या देश की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थीं, तो कभी औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक क्षमता को वैश्विक शक्ति का मुख्य आधार समझा गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेषकर शीतयुद्ध के दौर में, परमाणु हथियारों को सर्वोच्च शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक माना जाने लगा। ऐसा माना जाता था कि परमाणु क्षमता से संपन्न देश ही वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। किंतु 21वीं शताब्दी के आगमन ने इन सभी पारंपरिक धारणाओं को पीछे छोड़ दिया है। आज के दौर में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, तकनीकी नेटवर्क और समुद्री मार्गों ने शक्ति की परिभाषा को एक बिल्कुल नया और बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है। हाल के वर्षों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उभरी परिस्थितियों ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक दुनिया में केवल सैन्य सामर्थ्य ही निर्णायक नहीं है। किसी महत्वपूर्ण भौगोलिक मार्ग, संसाधन अथवा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण भी उतना

ही प्रभावशाली और रणनीतिक साधन बन सकता है। यही वह महत्वपूर्ण संदेश है जो ईरान की वर्तमान रणनीति के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने उभरकर आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री मार्ग है। भौगोलिक दृष्टि से यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। इस संकरे मार्ग का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे दुनिया के सबसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समुद्री निर्यात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। वैश्विक कच्चे तेल की कुल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा रोजाना इस संकरे जलमार्ग से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। इसके अलावा, तेल प्राकृतिक गैस के वैश्विक समुद्री व्यापार का भी एक बहुत बड़ा भाग इसी रास्ते से तय होता है। इसलिए होर्मुज केवल एक साधारण जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यदि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है या तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा और तात्कालिक प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों, समुद्री परिवहन लागत, औद्योगिक उत्पादन और दुनिया भर के उपभोक्ता बाजारों पर दिखाई देने लगता है। इस पूरे परिदृश्य में ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे इस क्षेत्र में एक विशिष्ट सामरिक महत्व प्रदान करती है। इस जलडमरूमध्य के उत्तरी तट पर ईरान का सीधा भौगोलिक प्रभाव है और इसी कारण वह लंबे समय से इस मार्ग को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति के रूप में देखता रहा है। जब भी पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध

लागाए गए या उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की अनदेखी की गई, तब उसने बार-बार यह संकेत दिया कि वह होर्मुज में जहाजों के आवागमन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कई अवसरों पर ईरान ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह चेतावनी भी दी है कि यदि उसके राष्ट्रीय हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया, तो वह इस मार्ग को पूरी तरह बंद करने अथवा यहाँ अतिरिक्त नियंत्रण स्थापित करने पर विचार कर सकता है। यहाँ से दुनिया के लिए एक नया भू-राजनीतिक संदेश निकलता है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भूगोल स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि किसी देश के पास कोई ऐसा विशिष्ट स्थान है जो वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति या सामरिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य है, तो वह देश अपनी सीमित सैन्य या आर्थिक क्षमताओं के बावजूद वैश्विक मंच पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रख सकता है। ईरान दशकों से भारी आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबावों का सामना कर रहा है, लेकिन होर्मुज पर उसकी सामरिक स्थिति उसे विश्व राजनीति में लगातार प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाए रखती है। विशाल परिपरिक शक्ति संतुलन को भी गंभीर चुनौती देती है। लंबे समय तक वैश्विक राजनीति में यह माना जाता रहा कि बड़ी सैन्य और परमाणु शक्ति रखने वाले देश किसी भी क्षेत्रीय संकट का समाधान अपने पक्ष में करने में सक्षम होते हैं। लेकिन होर्मुज का उदाहरण दिखाता है कि कठोर भौगोलिक वास्तविकताएं कई बार विशाल सैन्य शक्ति को भी सीमित कर देती हैं। यदि इस समुद्री मार्ग पर थोड़ा भी तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल एक क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए दुनिया के सबसे

शक्तिशाली देशों को भी यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करने से पहले कूटनीति, समझौतों और क्षेत्रीय संतुलन का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही, ईरान की इस रणनीति ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। ऊर्जा आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला है जिसके बिना उद्योग, परिवहन, कृषि और संचार जैसे लगभग सभी क्षेत्र ठप हो सकते हैं। जब किसी ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग पर संकट की मामूली आशंका भी उत्पन्न होती है, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव शुरू हो जाता है। इससे दुनिया भर के निवेशकों में चिंता बढ़ती है और सरकारें वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस प्रकार एक सीमित क्षेत्रीय तनाव भी व्यापक वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। इस परिस्थिति का प्रभाव केवल तेल उत्पादक या पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहता है। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोप के अनेक प्रमुख देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से पश्चिम एशिया के इसी मार्ग पर निर्भर हैं। यदि होर्मुज में कोई बाधा आती है तो इन विकासशील और विकसित देशों की ऊर्जा सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम राष्ट्र इस मार्ग को हमेशा खुला और सुरक्षित बनाए रखने के पक्षधर हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि यहाँ उत्पन्न होने वाला कोई भी संकट उनके घरेलू आर्थिक हितों को सीधे चोट पहुंचाएगा। ईरान के इस व्यवहार से यह भी स्पष्ट होता है कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल हथियारों के संचय की नहीं होगी। बीते दशकों में परमाणु हथियारों के

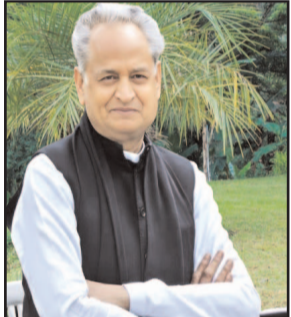
बावजूद गहलोल ने अपनी राजनीतिक सक्रियता में कोई कमी नहीं आने दी। हाल के महीनों में उनके कई स्पष्ट और बेबाक बयान राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार महावीर जैन कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति भले ही अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं कही जा सकती, लेकिन पार्टी के जनाधार को बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम अभी भी गहलोल प्रभावी ढंग से करते दिखाई देते हैं। जैन कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोल का लगभग सभी जाति, समाज और वर्ग में प्रभाव है, उसका एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के लिए उम्मीद है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोल को योजनाएं लागू थे, उनसका लाभार्थी वर्ग भी बहुत बड़ा है, जो उनके नेतृत्व में विश्वास करता है। मारवाड़ दौरे के दौरान जिस प्रकार विभिन्न स्थानों पर गहलोल का स्वागत हुआ, उसने राजनीतिक विक्षेपकों का ध्यान आकर्षित किया है। संयोगवश उसी समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी

पर नियंत्रण रखने वाले देशों का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार एक प्रकार की निर्भरता समाप्त होते ही दूसरी निर्भरता जन्म ले लेगी। यह पूरी स्थिति वैश्वीकरण की उस पारंपरिक अवधारणा को भी चुनौती देती है जिसके अनुसार वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी का प्रवाह स्वतंत्र और निर्बाध होना चाहिए। लेकिन जब इन महत्वपूर्ण मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में होने लगता है, तब वैश्वीकरण की नींव कमजोर पड़ने लगती है। कंपनियों और सरकारों के वैकल्पिक मार्गों, अतिरिक्त भंडारण और विविध स्रोतों की महंगी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। हालांकि ईरान का तर्क है कि वह केवल अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग एक रणनीतिक साधन के रूप में करता है, जबकि आलोचक इसे वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाने के लिए अब कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक प्रतिबंध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकते। यदि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना है, तो क्षेत्रीय देशों तथा बड़ी शक्तियों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक होगा। अंततः, ईरान के व्यवहार से यही निष्कर्ष निकलता है कि 21वीं शताब्दी में शक्ति का स्वरूप बहुआयामी हो गया है, जहाँ भौगोलिक स्थिति, समुद्री मार्ग, संसाधन और ऊर्जा नेटवर्क ही भविष्य की विश्व राजनीति की दिशा तय करेंगे।

## पद से बड़े कद के हैं गहलोल, मारवाड़ दौरे से फिर साबित

राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोल सदा सदा से लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज भले ही वे मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति और जनता, दोनों में उनका प्रभाव आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखाई देता है, जितना एक मुख्यमंत्री रहते हुए था। हाल ही में जालोर, पाली, सिरोही और उदयपुर सहित मारवाड़ क्षेत्र के विभिन्न जिलों के उनके दौरे ने यह संदेश दिया है कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद उनकी जनस्वीकार्यता में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। कांग्रेस संगठन भले ही वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर रहा हो, लेकिन गहलोल के कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ और स्थानीय स्तर पर

मिले स्वागत ने यह संकेत दिया कि वे आज भी राजस्थान कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली जननेताओं में शामिल हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का भी मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत और सामाजिक आधार को बनाए रखने में गहलोल की भूमिका अब भी केंद्रीय बनी हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोल ने हाल ही में उदयपुर, सिरोही, जालोर, पाली और जोधपुर जिलों का एक विस्तृत दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने संगठनिक बैठकों में भाग लिया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, रोड़ शौ किया और व्यापक पैमाने पर लोगों से मुलाकातें कीं। उनके इस सफर के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर समय-समय पर बहस होने के बावजूद उनका प्रभाव बरकरार बना हुआ है। यह भी तथ्य है कि कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ वर्षों में अशोक गहलोल और सचिन पायलट के बीच मतभेदों की चर्चा लगातार होती रही है। हालांकि इन परिस्थितियों के



अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। परिहार का मानना है कि गहलोल ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक अनुभव, संगठनात्मक कौशल और व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से एक ऐसा राजनीतिक आधार तैयार किया है, जो केवल पद पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर समय-समय पर बहस होने के बावजूद उनका प्रभाव बरकरार बना हुआ है। यह भी तथ्य है कि कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ वर्षों में अशोक गहलोल और सचिन पायलट के बीच मतभेदों की चर्चा लगातार होती रही है। हालांकि इन परिस्थितियों के

बावजूद गहलोल ने अपनी राजनीतिक सक्रियता में कोई कमी नहीं आने दी। हाल के महीनों में उनके कई स्पष्ट और बेबाक बयान राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार महावीर जैन कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति भले ही अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं कही जा सकती, लेकिन पार्टी के जनाधार को बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम अभी भी गहलोल प्रभावी ढंग से करते दिखाई देते हैं। जैन कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोल का लगभग सभी जाति, समाज और वर्ग में प्रभाव है, उसका एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के लिए उम्मीद है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोल को योजनाएं लागू थे, उनसका लाभार्थी वर्ग भी बहुत बड़ा है, जो उनके नेतृत्व में विश्वास करता है। मारवाड़ दौरे के दौरान जिस प्रकार विभिन्न स्थानों पर गहलोल का स्वागत हुआ, उसने राजनीतिक विक्षेपकों का ध्यान आकर्षित किया है। संयोगवश उसी समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी

पाली और सिरोही क्षेत्र के दौर पर थे, जिससे दोनों नेताओं के जनसंपर्क कार्यक्रमों की तुलना स्वाभाविक रूप से होने लगी। वरिष्ठ पत्रकार बालमुकुंद शर्मा कहते हैं कि गहलोल के कार्यक्रमों में जिस प्रकार का उत्साह और जनसहभागिता दिखाई दी, उसने यह स्पष्ट किया कि वे केवल कांग्रेस के नेता भर नहीं, बल्कि एक स्थापित जनाधार वाले राजनेता हैं। शर्मा बताते हैं कि तीन बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर जो नेटवर्क विकसित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत संपर्क बनाए, उसका लाभ उन्हें आज भी मिलता दिखाई देता है। यह कारण है कि सत्ता परिवर्तन के ढाई वर्ष बाद भी उनके प्रति लोगों का जुड़ाव कम नहीं हुआ है। राजस्थान की राजनीति में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच निरंतर संवाद बनाए रखते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पद पर न रहते हुए भी उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मारवाड़ का हालिया दौरा वस्तुतः

अशोक गहलोल के राजनीतिक कद के पुनः पुष्टि का अवसर बन गया। यह दौरा केवल जनसभाओं और स्वागत कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि राजस्थान की राजनीति में गहलोल अब भी एक केंद्रीय शक्ति हैं। राजनीति के जानकारों का निष्कर्ष है कि राज्य में कांग्रेस के भविष्य की किसी भी रणनीति में अशोक गहलोल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विक्षेपक निरंजन परिहार कहते हैं कि सत्ता से बाहर रहने के बावजूद यदि किसी नेता को लगातार व्यापक जनसमर्थन, कार्यकर्ताओं का उत्साह और राजनीतिक प्रासंगिकता प्राप्त हो रही है, तो वह उसके लंबे राजनीतिक निवेश और जनविश्वास का परिणाम होता है। मारवाड़ दौरे ने एक बार फिर साबित किया है कि अशोक गहलोल का राजनीतिक प्रभाव केवल पद तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राजस्थान की राजनीति के स्थायी वास्तविकताओं में से एक बन चुका है।

## इमारतें ऊंची हुईं, सुरक्षा क्यों बौनी रह गई?



-सुरज गर्ग

लखनऊ की घटना ने देश को झकझोर दिया, लेकिन सच यह है कि यह किसी एक शहर की त्रासदी नहीं है। दिल्ली की रंग गलियां हों, मुंबई की ऊंची इमारतें, कोलकाता के पुराने बाजार, सूरत की फैक्ट्रियां, हैदराबाद के व्यावसायिक परिसर, बेंगलुरु के स्टार्टअप हब, जयपुर, पटना, भोपाल, कानपुर, वाराणसी, इंदौर या गुवाहाटी-भारत का शायद ही कोई बड़ा शहर ही जहां सुरक्षा नियमों से समझौता कर बनाई गई इमारतें मौत का इंतजार न कर रही हों। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं आग अभी लगी नहीं है और कहीं आगला शॉर्ट सर्किट अभी होना बाक़ी है। देश में पिछले दो दशकों के बड़े अग्निकांडों का इतिहास बताता है कि हर त्रासदी के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, दोषियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, कुछ अधिकारी निलंबित होते हैं और फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन व्यवस्था का चरित्र नहीं बदलता। यही कारण है कि हर नया हादसा पिछले हादसे की कार्बन कॉपी बनकर सामने आता है। सबसे

चिंताजनक तथ्य यह है कि भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ सुरक्षा संस्कृति विकसित हो रही हो सकी। शहर ऊंचे हो गए, इमारतें आधुनिक हो गईं, लेकिन सोच अब भी पुरानी है। भवन निर्माण के समय सबसे पहले जिस चीज की बलि दी जाती है, वह है सुरक्षा। बिल्डर लागत बचाता है, संचालक जगह बचाता है, अधिकारी जिम्मेदारी बचाता है और अंततः नागरिक अपनी जान गंवाता है। आज देश के अधिकांश शहरों में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिन्हें आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन उनमें क्वीक्री सेंटर, हॉस्टेल, अस्पताल, बैंकवेट हॉल, गोदाम, कॉल सेंटर, कार्यालय, क्लबिंग और प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। भवन की क्षमता पचास लोगों की होती है, लेकिन रोजाना वहां दो सौ से तीन सौ लोग मौजूद रहते हैं। बिजली की अतिरिक्त लोडिंग, बंद खिड़कियां, सक्करे रास्ते, ज्वलनशील सामग्री, अवैध निर्माण और इमरजेंसी एजिजट की अभाव-यह लगभग हर शहर की सामान्य तस्वीर है। विडंबना यह है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता, तब तक किसी विभाग की यह अवैधता दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही आग लगती है, उसी इमारत की फाड़लों से वर्षों पुरानी अनियमितताएं निकलने लगती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि व्यवस्था अनजान नहीं थी, बल्कि मौन थी। और कई बार यह मौन संयोग नहीं, बल्कि सुविधा को परिणाम होता है। फायर सेफ्टी को



किसी भी शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि उनमें रहने और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा से होती है। दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश शहर आज ऐसे कंक्रीट के जंगलों में बदल चुके हैं, जहां विकास की चमक के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी का अंधेरा छिपा हुआ है। लखनऊ का भीषण अग्निकांड इसी कड़वी सच्चाई का भयावह उदाहरण है। यह केवल एक इमारत में लगी आग नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता है, जिसने वर्षों तक नियमों के उल्लंघन को सामान्य मान लिया। हर बड़े हादसे के बाद जांच, निलंबन और मुआवजे की औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन व्यवस्था की कार्यशैली जस की तस बनी रहती है। यदि इस त्रासदी को केवल लखनऊ तक सीमित समझने की भूल की गई, तो देश का कोई भी शहर अगली भयावह खबर बन सकता है। अब समय संवेदना व्यक्त करने का नहीं, बल्कि सुरक्षा को शासन और समाज दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का है

हो जाता है। आज आवश्यकता केवल दोषियों की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भवन सुरक्षा सुधार अभियान की है। जिस प्रकार सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और टीकाकरण को राष्ट्रीय मिशन बनाया गया, उसी प्रकार अग्नि सुरक्षा को भी जन आंदोलन बनाना होगा। हर राज्य में एक समग्रबद्ध अभियान चलाकर सभी व्यावसायिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक भवनों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराया जाना

चाहिए। डिजिटल अनुमति प्रणाली, ऑनलाइन निरीक्षण रिकॉर्ड सार्वजनिक सुरक्षा रेटिंग और नागरिक शिकायत तंत्र को मजबूत किए बिना सुधार अधूरा रहेगा। यह भी उतना ही आवश्यक है कि समाज स्वयं भी जागरूक हो। माता-पिता अपने बच्चों को जिस कोचिंग या संस्थान में भेजते हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों रखते हैं। कर्मचारियों को भी यह समझना होगा कि आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा अभ्यास केवल औपचारिक शब्द नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी हैं। सभ्यता का विकास केवल ऊंची इमारतों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि उन इमारतों के भीतर रहने और काम करने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं। यदि भारत 'विकसित राष्ट्र' बनने का सपना देख रहा है, तो उसे 'सुरक्षित राष्ट्र' बनने की दिशा में भी उतनी ही गंभीरता से कदम बढ़ाने होंगे। लखनऊ की राख से उठता धुआं केवल उत्तर प्रदेश के आसमान में नहीं फैला है। वह पूरे भारत की अंतरात्मा से एक प्रश्न पूछ रहा है- क्या अगली आग भी किसी जांच किये जाना चाहिए। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि किसी दुर्घटना के बाद जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित न रहे। इन समय आ गया है कि भवन निर्माण, नगर नियोजन, अग्निशमन विभाग और विकास प्राधिकरणों के बीच मौजूद प्रशासनिक खामियों को दूर किया



## KEM अस्पताल नामांतरण मामला, किंग एडवर्ड गुलामी के दौर का प्रतीक : मंगल प्रभात लोढ़ा

मुंबई (उत्तरशक्ति)। किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल के नाम परिवर्तन के संबंध में आज विधान परिषद में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। लोढ़ा ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटिश शासनकाल भारत के शोषण का काल था। उन्होंने कहा, किंग एडवर्ड भारत के लिए गौरव का विषय नहीं है, बल्कि वह गुलामी के दौर का प्रतीक है। आगे उन्होंने कहा, किंग एडवर्ड ने भारत को गुलाम बनाया था और देश की संपत्ति लूटकर इंग्लैंड ले गया था। यह कहना कि किंग एडवर्ड ने धन दिया था, पूरी तरह भ्रामक है। इस संदर्भ में उन्होंने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा, लाखों भारतीयों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार किंग एडवर्ड कसाब जैसा व्यक्ति था। किंग एडवर्ड के नाम का समर्थन करने वालों की हम निंदा करते हैं। केईएम के नाम परिवर्तन के लिए हमने तीन नामों के विकल्प दिए हैं और सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित तीनों नामों में से किसी भी विकल्प का चयन किया जाए, उसका संक्षिप्त रूप केईएम ही रहेगा। ट्रम्प टॉवर का नाम बदलने को लेकर प्रश्न उठाए जाने पर माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि ट्रम्प नाम केवल व्यावसायिक साझेदारी के कारण दिया गया है और इसका किसी भी प्रकार के गौरव या महामांडल से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान विधान परिषद सदस्य श्री मिलिंद नावेंकर ने माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के व्यवसाय पर प्रश्न उठाया। इसका जवाब देते हुए लोढ़ा ने कहा, मेरा व्यवसाय पूरी दुनिया जानती है और मेरी आय का स्रोत भी सभी को ज्ञात है। लेकिन आपका व्यवसाय क्या है, यह हमें नहीं पता। फिर भी आप मुझे बड़ी गाड़ी में घुमते हैं, ऐसा उन्होंने पलटवार करते हुए कहा।

## सांस लेने में गंभीर परेशानी के पीछे छिपी दुर्लभ तंत्रिका संबंधी बीमारी की पहचान

मुंबई / कोलकाता। झारखंड की एक किशोरी को अचानक सांस लेने में गंभीर परेशानी होने पर मणिपाल हॉस्पिटल ब्रॉडवे में भर्ती कराया गया। शुरूआत में डॉक्टरों को लगा कि वह फेफड़ों के गंभीर संक्रमण से पीड़ित है। लेकिन उपचार शुरू होने के बावजूद उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। इसके बाद डॉक्टरों ने मामले की गहराई से जांच की और पाया कि वह मायस्थेनिया ग्रेविस नामक एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण उसे मायस्थेनिक क्राइसिस हुआ था। इस स्थिति में मांसपेशियों की कमजोरी सांस लेने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। समय पर सही बीमारी की पहचान और समन्वित उपचार के जरिए डॉ. देवराज यादव, डायरेक्टर - पल्मोनोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल कोलकाता, तथा डॉ. वैभव सेठ, कंसल्टेंट-न्यूरोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल ब्रॉडवे, ने मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया। यह मामला जटिल चिकित्सकीय परिस्थितियों में समय रहते सही निदान और विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों के महत्व को दर्शाता है।

मई महीने में किशोरी को एक रेलवे अस्पताल से गंभीर सांस संबंधी तकलीफ के कारण मणिपाल हॉस्पिटल ब्रॉडवे भेजा गया था। उसके शुरूआती लक्षणों और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों को न्यूमोनिया की आशंका हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए नर्सों के माध्यम से एंटीबायोटिक उपचार शुरू किया गया। हालांकि कुछ ही घंटों में उसकी सांस लेने की परेशानी काफी बढ़ गई और उसकी श्वसन क्षमता प्रभावित होने लगी, जिसके कारण उसे वेंटिलेटर की सहायता देनी पड़ी। आगे की जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि सीटी स्कैन में दिखाई देने वाली फेफड़ों की स्थिति और मरीज की गंभीर हालत के बीच काफी अंतर था। फेफड़ों में व्यापक क्षति नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। इसी वजह से डॉक्टरों ने अन्य संभावित कारणों की जांच शुरू की।

विस्तृत जांच में मरीज की मांसपेशियों में काफी कमजोरी और चलने-फिरने की क्षमता में कमी पाई गई, जिससे किसी तंत्रिका-मांसपेशी संबंधी बीमारी की आशंका हुई। डॉक्टरों ने मायस्थेनिया ग्रेविस और गिलियन-बारे सिंड्रोम जैसी बीमारियों की संभावना पर विचार किया। आगे की जांच में पुष्टि हुई कि मरीज मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ मायस्थेनिक क्राइसिस से पीड़ित थी। मायस्थेनिया ग्रेविस एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से नर्सों और मांसपेशियों के बीच होने वाले संदेशों के आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न करती है। इसके कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। आमतौर पर इसके लक्षणों में पलकों का झुक जाना, निगलने में कठिनाई या हाथ-पैरों में कमजोरी शामिल होती है। गंभीर मामलों में सांस लेने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में मायस्थेनिक क्राइसिस हो सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है और मरीज को गहन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है।

## ज्येष्ठ साहित्यकारों व कलाकारों से मानधन सम्मान योजना का लाभ लेने का आह्वान

पालघर (उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक एवं कलाकार मानधन सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ साहित्यकारों एवं कलाकारों से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। यह जानकारी जिला परिषद पालघर के ग्रामपंचायत विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील ने दी।

उन्होंने बताया कि साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में लंबे समय तक उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ साहित्यकारों व कलाकारों को सम्मानित करने तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह योजना संचालित कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नियमित मानधन प्रदान किया जायेगा और उनके कार्यों का सम्मान भी किया जायेगा।

इच्छुक पात्र लाभार्थियों को आपले सरकार सेवा केंद्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संबंधित समूह विकास अधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से जमा करनी होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें। पात्र वरिष्ठ साहित्यकारों व कलाकारों से निधारित अवधि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। इस योजना से साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को आर्थिक संबल मिलने के साथ-साथ उनके कार्यों को शासन स्तर पर उचित सम्मान और पहचान भी प्राप्त होगी।

# हिंदी भाषा रत्न सम्मान से अलंकृत हुए प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी

सतारा/मुंबई (उत्तरशक्ति)। राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल एवं सतारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रभाषा भवन, शिवाजी पेठ, सतारा में आयोजित एक गरिमामय समारोह में हिंदी, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी को प्रतिष्ठित हिंदी भाषा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में प्रदेशभर से आए शिक्षकों, साहित्यकारों, शोधकर्ताओं एवं हिंदी सेवियों ने उनकी उल्लेखनीय सेवाओं की मुक्त कंठ से सराहना की।

प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं शोध आचार्य हैं। इसके साथ ही वे हिंदी साहित्य भारती, महाराष्ट्र के अध्यक्ष तथा भारतीय

जनता पार्टी, मुंबई के प्रवक्ता के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा, समाज और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है।

मुंबई के अनेक प्रतिष्ठित दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों में उनके नियमित स्तंभ, विचार लेख और समसामयिक विश्लेषण प्रकाशित होते हैं, जिन्हें पाठकों का व्यापक स्नेह और सम्मान प्राप्त है। करियर मार्गदर्शन, शिक्षा नीति, राष्ट्रभाषा, सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय विचार जैसे विषयों पर उनकी लेखनी विशेष रूप से चर्चित रहती है। साहित्य जगत में भी वे एक सशक्त चिंतक, प्रेरक वक्ता और सक्रिय लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

समारोह में वक्ताओं ने कहा कि

## मीरारोड में बिल्डिंग का छज्जा गिरा, बड़ा हादसा टला

मीरारोड। बुधवार रात्रि हुई भारी वर्षा के दौरान गवर्नरदेवी स्थित राजश्री शॉपिंग सेंटर में एक बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे के प्रयासों से अग्निशमन विभाग की टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया। अग्निशमन कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भवन के शेष जर्जर एवं खतरनाक हिस्सों को सुरक्षित रूप से हटवाया तथा गिरे हुए मलबे की सफाई कर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया। इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने भी प्रशासन और बचाव दल का भरपूर सहयोग किया, जिससे राहत एवं सुरक्षा कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सका। नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों, स्थानीय नागरिकों तथा सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में नागरिक जर्जर इमारतों और ढीले निर्माण हिस्सों से सतर्क रहें तथा किसी भी खतरे की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।

## पीपीएफएस पेंशन ने अंधेरी, मुंबई में किया अपने पहला ऑफिस का शुभारंभ

मुंबई (उत्तरशक्ति)। पीपीएफएस पेंशन ने आज अंधेरी में अपने पहले ऑफिस का शुभारंभ किया। यह कंपनी के विस्तार में एक अहम पड़ाव है, जिससे मुंबई में इसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है। नया कॉर्पोरेट ऑफिस 701, 7th फ्लोर, 349 बिजनेस पॉइंट कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई 400 069 पर है। ऑफिस का विमोचन पीपीएफएस पेंशन के प्रस्तावित चीफ एजीक्यूटिव ऑफिसर पृथ्वीनाथ रेड्डी और प्रस्तावित चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अभिषेक गोकनका की मौजूदगी में हुआ। इस इवेंट में पीपीएफएस ग्रुप के जाने-माने लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए, पृथ्वीनाथ रेड्डी ने कहा, हम मुंबई में अपना पहला ऑफिस खोलकर बहुत खुश हैं। हम अभी अपनी नेशनल पेंशन सिस्टम सर्विसेज शुरू करने के लिए जरूरी ऑपरेशनल और रेगुलेटरी प्रोसेसिंग पूरे कर रहे हैं। मिस्टर रेड्डी ने आगे कहा, अंधेरी में यह ऑफिस इन्वेस्टमेंट के साथ बातचीत करने और नेशनल पेंशन सिस्टम के



जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक खास हब के तौर पर काम करेगा। साथ ही, यह पीपीएफएस पेंशन के लंबे समय तक पैसा बनाने के कमिटमेंट को और मजबूत करेगा।

## पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राइव को मिला उत्साहजनक प्रतिसाद, 177 युवाओं ने लिया हिस्सा

पालघर (उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, पालघर द्वारा बुधवार 24 जून 2026 को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राइव को युवाओं का उत्साहजनक प्रतिसाद मिला। रोजगार मेले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने पहुंचे।

इस प्लेसमेंट ड्राइव में चार नामांकित कंपनियों ने भाग लेते हुए कुल 110 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित की। रोजगार मेले के दौरान 177 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 30



उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन तथा 5 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। रोजगार मेले में ब्लूस्टार लिमिटेड, एशियन पेट्स, इंटरनेशनल वायरनेटिंग तथा युनिकेयर हेल्थकेयर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पालघर, रोजगार मेला समन्वय समिति के सदस्य तथा जिला कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संपूर्ण कार्यक्रम रोजगार मेला नोडल अधिकारी रविंद्र सुरवसे तथा सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उपस्थित युवाओं ने रोजगार मेले की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे उपक्रमों से स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।



प्रो. डॉ. तिवारी ने अपने अध्यापन, शोध, साहित्य सृजन और जनजागरण के माध्यम से हिंदी भाषा के संवर्धन एवं प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

## रिक्शा में सफर कर रही महिला से गहने चोरी करने वाली शातिर महिला गिरफ्तार

वसई (उत्तरशक्ति)। रिक्शा में सफर कर रही महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गहने चोरी करने वाली शातिर महिला को मानिकपुर पुलिस की अपराध जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख रुपये मूल्य का माल बरामद किया गया है। साथ ही, महिला आरोपी से विभिन्न पुलिस थानों के 10 अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है। प्राण जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता श्रीमती मेरी पॉल सिरवेल ने मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 जून 2026 को दोपहर के समय वह गोखोवरे नाका से वसई स्टेशन की ओर रिक्शा से जा रही थीं। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उनके बैग से लगभग 80 ग्राम वजन की सोने की चेन तथा चार सोने की चूड़ियां चोरी कर लीं। इस मामले में मानिकपुर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक

## मानिकपुर अपराध जांच टीम की बड़ी सफलता



308/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 303(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त परिक्षेत्र-2 अशोक विरकर तथा सहायक पुलिस आयुक्त वसई नवनाथ घोगरे के मार्गदर्शन में मानिकपुर और वसई पुलिस की अपराध जांच शाखा ने जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण तथा तकनीकी एवं गोपनीय

## साकीनाका के खाड़ी क्रमांक तीन गंदे पानी के जमाव से नागरिक त्रस्त

मुंबई (उत्तरशक्ति)। केंद्र तथा राज्य सरकार और मनपा जहां एक तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला रही है वहीं साकीनाका के खाड़ी क्रमांक तीन वार्ड क्रमांक १६१ की झोपड़पट्टियों में शुरूवाती बरसात में ही गंदे पानी के जमाव से नागरिक और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के शुरू होने के पूर्व ही जहां मनपा की ओर से जलजमाव वाले इलाकों में पानी निकासी के लिए मोटर लगाया गया है वहीं खाड़ी क्रमांक तीन में जलजमाव होने के बाद भी मोटर नहीं बिठाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले तीन दशक से साकीनाका के खाड़ी क्रमांक तीन और मिलिंद नगर झोपड़पट्टी में बरसात के दौरान हमेशा ही जलजमाव हुआ करता है। स्थानीय युवा समाजसेवक और शिदि गुट के शिवसैनिक प्रदीप बंड ने बताया कि मिलिंद नगर और राजीव नगर झोपड़पट्टी से बरसात के दौरान सुंदरबाग और हिमालय सोसाइटी के सामने की पहाड़ी का गंदा पानी बहकर आता है जिससे यहां

## बिबंदी में नाला सफाई की खुली पोल, 2.44 करोड़ खर्च, फिर भी पहली बारिश में जलभराव, मजदूर कचरा बहाने में जुटे!

बिबंदी (उत्तरशक्ति)। मानसून की पहली बारिश ने ही बिबंदी महानगरपालिका के नाला सफाई अभियान की हकीकत उजागर कर दी है। एक ओर बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर शहर के कई इलाकों में जलभराव और गटर जाम की समस्या ने मनपा प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर के घुंघटनगर, शांतिनगर, तीनबत्ती, भाजी मार्केट सहित कई क्षेत्रों में पहली ही बारिश में पानी जमा हो गया। वहीं नवी बस्ती क्षेत्र में गटर जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि परेशान नागरिकों को खुद ही गटर की सफाई के लिए मैदान में उतरना पड़ा। गौरतलब है कि बिबंदी मनपा ने इस वर्ष नाला सफाई कार्य के लिए 2 करोड़ 44 लाख 65 हजार रुपये का ठेका विभिन्न ठेकेदारों को दिया था। मानसून पूर्व नालों की सफाई पूरी करने और जलभराव रोकने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। मनपा आयुक्त अनमोल सागर और महापौर नारायण चौधरी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि

सफाई नहीं तो बिल नहीं, लेकिन पहली ही बारिश में हालात देखकर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पानी निकासी व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई? सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था के नाले में उतरकर जमा कीचड़ और कचरे को बाहर निकालने के बजाय पानी के बहाव में आगे धकेलते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य ने केवल सफाई कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नाला सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। यदि समय रहते नालों से गाद और कचरा पूरी तरह निकाला गया होता तो

समर्पित बताते हुए कहा कि बिबंदी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और जनभावनाओं की आत्मा है। वह उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी वे हिंदी के प्रचार-प्रसार और साहित्यिक उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

समारोह के अंत में उपस्थित शिक्षकों, विद्वानों और गणमान्य अतिथियों ने प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी को बधाई देते हुए उनके दीर्घ समर्पित और प्रेरणादायी योगदान के हिंदी जगत की अमूल्य धरोहर बताया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह सम्मान हिंदी भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति उनके अथक समर्पण का सशक्त प्रमाण माना गया।

## देवी से पूछताछ कर उसके कब्जे से करीब 8 लाख रुपये मूल्य की 80 ग्राम सोने की चेन और चार सोने की चूड़ियां बरामद कीं। वहीं, आरोपी सोनू हुकुम सिंह के पास से एक मोटरसाइकिल समेत लगभग 4 लाख रुपये मूल्य का अन्य सामान जब्त किया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला मंजू देवी सोनू सिंह उर्फ बावरी अन्य पुलिस थानों में दर्ज 10 मामलों में भी शामिल रही है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अशोक विरकर, सहायक पुलिस आयुक्त नवनाथ घोगरे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हरिलाल जाधव के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक विकास सुकलवाड, सचिन दोरकर, अनिल चव्हाण, शमेश चंदनशिवे, मंगेश जगताव, गोविंद लवटे, आनंद गडेवा, प्रवीण कांडे, भालचंद्र बाजुल और अमोल बर्डे सहित अपराध जांच टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दी।

जानकारी के आधार पर पुलिस ने महिला आरोपी मंजू देवी सोनू सिंह उर्फ बावरी (32), निवासी नवनाथ पश्चिम, जिला पालघर, मूल निवासी फरीदाबाद, हरियाणा को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी महिला का पति सोनू हुकुम सिंह भी इस अपराध में शामिल है। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी मंजू

## निचले इलाकों में मोटर पम्प बिठाने की मांग

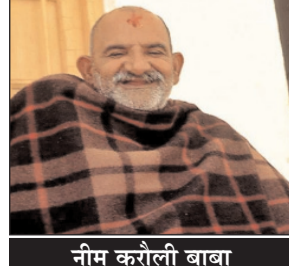


पड़ता है। बता दें कि मंगलवार से शुरू हुई बारिश में नागरिकों को आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय युवा समाजसेवक और शिदि गुट के शिवसैनिक प्रदीप बंड ने बताया कि मिलिंद नगर और राजीव नगर झोपड़पट्टी से बरसात के दौरान सुंदरबाग और हिमालय सोसाइटी के सामने की पहाड़ी का गंदा पानी बहकर आता है जिससे यहां

## जलजमाव हुआ करता है। बंड के अनुसार बरसात के दौरान यहां हमेशा ही जलजमाव हुआ करता है लेकिन मनपा द्वारा पानी निकासी के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। शिवसैनिक प्रदीप बंड ने कुर्ला एल वार्ड के संबंधित अधिकारियों से मिलिंद नगर और राजीव नगर झोपड़पट्टी में पानी निकासी के लिए मोटर बिठाने की मांग की है।



पहली ही बारिश में शहर के कई हिस्सों में जलभराव की नौबत नहीं आती। नागरिकों का कहना है कि कागजों पर सफाई दिखाकर सरकारी धन की बर्बादी की गई है। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब शहरवासियों की निगाहें मनपा आयुक्त और महापौर पर टिकी हैं। सवाल यह है कि जब स्वयं प्रशासन ने रसफाई नहीं तो बिल नहीं कर नापा दिया था, तो क्या अब नाला सफाई में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? या फिर हर साल की तरह इस बार भी करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद जवाबदेही तय किए बिना मामला उठे बरतने में डाल दिया जाएगा?



नीम करौली बाबा

**उत्तरशक्ति**

\* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति

\* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा

\* प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्दु

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

**पत्राचार कार्यालय :**

उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)

मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल, ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37

मो.- 9554493941

email ID- uttarshaktinews@gmail.com

**प्रजापति** 93245 26742

**फॅब्रीकेशन अॅण्ड गिलवर्क्स** 98200 55193

**PRAJAPATI** 93227 55403

**FABRICATION & GRILL WORKS**

MANUFACTURERS OF

COMPOUND GATES, MS GRILLS, WATER TANKS, ROLL SHUTTER, COLLAPSIBLE DOOR & ALLUMINIUM SLIDING WINDOW

SHOP NO. 101, SAVERA CHS., LAST BUS STOP, VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI-400053. GST No. : 27ANKPP6297R1ZP



